के अंतर्गत यह अधिकार प्रदत्त है कि वह किसी की भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन, आज जो विभिन्न प्रदेशों में देखने को मिल रहा है और जो सूचनाएं आ रही हैं, वे यह है कि उद्योगों के लिए और गैर सरकारी उपयोग के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

श्री सभापति: यह क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है, सर।

श्री सभापति: जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: भूमि अधिग्रहण कानून को रिवेम्प करते समय ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं, नहीं, क्वेश्चन वह नहीं है। Next Question. Question No. 226.

Rise in naxal activities

226. SHRI VIJAY J. DARDA: ††
SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the naxal violence continues unabated with rising number of incidents causing loss of life and property over the years, the situation has worsened despite claims of putting in place socio-economic measures with higher allocation in affected areas and refurbishing of police forces with right intelligence inputs;

(b) if so, whether according to latest Government figures, the number of violent incidents increased from 1465 in 2002 to 1608 in 2005 and till October last, 1272 incidents were reported; and

(c) what concrete steps and measures Government have taken to check the naxalites' activities in the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) to (c) The Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The overall magnitude of naxal violence in terms of number of incidents has shown a decline by 6.15% in 2006 as compared to 2005. In the year 2006, the State of Chhattisgarh alone accounted for 47.38% of the total incidents of naxal violence and 57.22% of total casualties. In the rest of the country, the overall level of naxal violence showed a significant decline in the year 2006, as compared to 2005.

---

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Vijay J. Darda.

(c) In order to check the growth of naxalite activities in the country, the Government has addressed the problem both on security and development fronts. The measures include deployment of the Central Para Military Forces to supplement the effort of the State Governments. 33 battalions of CPMFs have been deployed on anti-naxal duties, assisting the State Police Forces. 29 India Reserve Battalions have been sanctioned. Under the Scheme for Modernization of State Police Forces, assistance for modern weaponry, latest telecommunication equipments and other related infrastructure is provided to the naxal affected States. The total asistance provided towards in last six years, is about Rs. 4000 crores. In addition, security related expenditure amounting to over Rs. 210 crores has so far been disbursed to these States towards expenditure on ammunition, mobility of police personnel, rehabilitation of surrendered naxalites, *ex-gratia* relief to killed civilians and insurance of the security personnel. On the development side financial assistance of the order of over Rs. 1500 crores has been provided to the naxal affected States under the Backward District Initiative (BDI) component of the Rashtriya Sam Vikas Yojna. Similar development assistance is available to naxal affected States under the Backward Regions Grant Fund (BRGF) Scheme.

श्री विजय जे॰ दर्डा: सभापति महोदय, नक्सली गतिविधियों से सिर्फ एक प्रदेश ही नहीं, बल्कि कई प्रदेशों के लोग परेशान हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में ही इनकी गतिविधियां क्यों ज्यादा बढ़ी हैं।

श्री शिवराज वी॰ पाटील: श्रीमन, यह बात सही है कि सबसे ज्यादा नक्सली गतिविधियां छत्तीसगढ़ में बढ़ी हैं, 47% incidents बढ़े हैं और 56% killings बढ़े हैं। इसका कारण एक तो यह है कि वहां पर झाड़ियां और पहाड़ियां बहुत हैं और नक्सलवादी उनमें जाकर आसानी से जो करना चाहते हैं, वह कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो साधन दिए गए हैं, उनका साइंटिफिकली इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है-मैप लेकर, कहां, पर एक्शन लेना है, उसे देखकर, कहां पर डेवलपमेंट करना है, उसे देखकर और दूसरी पद्धति से कैसे करना है, इसे देखकर करना जरूरी है। शायद इस प्रकार की नीति उस सरकार को अपनानी पड़ेगी। तीसरी बात वहां पर यह है कि कुछ डेवलपमेंट का काम उस तरीके से नहीं हुआ है, जिस तरीके से शहरों में हुआ है और इसलिए भी वहां पर आक्रोश ज्यादा है। हमारी दृष्टि में ये कारण हैं। इसके बावजूद भी हम किसी स्टेट गवर्नमेंट को यह नहीं कहते हैं कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, यह इस वजह से हो रहा है। उनकी कुछ तकलीफात हैं, उनको समझकर उनको मदद करने का हमारा नज़रिया है और वह हम करते रहेंगे।

श्री विजय जे॰ दर्डा: सर, मेरा दूसरी सप्लिमेंट्री यह है कि नक्सलवादियों की गतिविधियों के कारण समस्त उद्योगों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सरकार ने अनेक राज्यों को coal blocks अलॉट किए हैं, mineral blocks अलॉट किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे वहां पर न बिजली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, न स्टील प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्योंकि उस जमीन पर जब भी वे लोग एक्टिविटीज़ करने के लिए जाते हैं तो उन्हें नक्सलवादियों का डर लगा रहता है और यहां तक कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वे भी उनको पूरा संरक्षण नहीं दे पा रही हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है और देश में बिजली की कमी तथा स्टील की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या आप उन उद्योगपतियों को सहयोग देंगे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, यही बात हम बार-बार इस सदन में कहते आ रहे हैं। हमने कहा नक्सलवाद बहुत बढ़ रहा है, हद से बढ़ गया है, बहुत से जिलों में पहुंचा है। ये सारे आंकड़े जो दिए जा रहे हैं, वे इस ढंग से दिए जा रहे हैं जैसे कि यह कोई एक भयानक चीज हो रही है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि इससे सब लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है और जो स्टेट यह कहती है कि हमारे यहां नक्सलवाद बहुत बढ़ गया है, नेचुरली वहां पर जाने के लिए लोग डरते हैं। इसलिए जो भी ऐसी बात हम कहते हैं कि 77 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ या 160 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, उसे समझकर कहना जरूरी है। जब हमने कहा कि यह डिस्ट्रिक्ट की बात है, एक गांव में हुआ तो डिस्ट्रिक्ट समझेंगे। हमने कहा कि एक पुलिस थाने में हुआ, पुलिस थाने के अगर आप आंकड़े लेंगे तो वह 3%, 3.5% तक आ जाता है और जब डिस्ट्रिक्ट्स के आंकड़े लिए जाते हैं तो 30% तक चला जाता है। तो यह जरूरी है कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: गृह मंत्री जी, क्षमा करें। भारत सरकार की जो पुस्तकें हैं, उनमें लिखा हुआ है कि कितने डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हैं ...(व्यवधान)...

श्री शिवराज वी॰ पाटील: श्रीमन्, बार-बार आपकी तरफ से यह प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपके साथ ...(व्यवधान)... मगर जो किताबें दी गई ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आपने यह कहा था, उस पर मैंने भी ऐतराज़ किया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर नहीं किया गया है।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, हमको चेयर से पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना बहुत मुश्किल होता है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मैं चेयर की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: सर, जो किताबें हम दे रहे हैं, उसे वे पढ़ ही नहीं रहे हैं और अगर उन किताबों को न पढ़ते हुए ही अपना मत बना रहे हैं और डर फैला रहे हैं तो उसका परिणाम तो हमारे ऊपर पड़ेगा ही। मैं तो यह कह रहा हूं, मैंने बार-बार यहां पर कहा है ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: यह बात आप चेयर को कह रहे हैं? यह आप कैसी बात कह रहे हैं?

श्री सभापति: आप बैठिए, बैठिए ...(व्यवधान)... आप छोड़िए इस बात को ...(व्यवधान)... वह यह नहीं कह रहे हैं ...(व्यवधान)... वह यह बात नहीं कह रहे हैं ... (व्यवधान)... वह यह नहीं कह रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, यह आपके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो दूसरे सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे?

श्री सभापति: नहीं, मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है ...(व्यवधान)... मेरे साथ उनका व्यवहार ठीक है ...(व्यवधान)...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: When the Chair is not objecting to it, you have no business to object to it? ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: जब मुझे ही कोई आपत्ति नहीं है, तब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं ...(व्यवधान)...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: You are putting words in his mouth...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: नहीं-नहीं, सर, आपको आपत्ति हो या न हो, लेकिन हमें तो है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं है, नहीं है ...(व्यवधान)... आप पहले मेरी बात सुनिए, वह जो कह रहे हैं ...(व्यवधान)... इसमें कोई गलती नहीं है ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, यह आपका बड़प्पन है कि आप यह कह रहे हैं कि आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने एक पुस्तक का उद्धरण दे कर पूछा, उस पर वह यह कह रहे हैं कि किताबें पढ़ते नहीं हैं और अपना मत बनाते हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं, यह उन्होंने मेरे लिए नहीं कहा है ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: और किसके लिए कहा है?

श्री सभापति: यह उन्होंने मेरे लिए नहीं कहा है ...(व्यवधान)... एक मिनट, आप बैठिए ... (व्यवधान)... एक मिनट, पहले आप सुन लीजिए ...(व्यवधान)... आप बैठिए, बैठिए ... (व्यवधान)... प्लीज़, बैठिए ...(व्यवधान)... मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि इनसे मेरी इस विषय पर चर्चा होती रहती है और हम पुस्तकें पढ़ते रहते हैं ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मैं भी तो वही बात कह रही हूं, क्योंकि पुस्तक का उद्धरण तो आप ही दे रहे हैं, उस पर वह यह कह रहे हैं कि पुस्तक पढ़ते नहीं हैं और अपना मत बनाते हैं। आप चाहे आपत्ति न करें, पर यह बात आपत्तिजनक है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं, नहीं, यह इसलिए नहीं कहा गया है ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: अच्छा आप इतना करें कि यह टिप्पणी निकलवा दें ...(व्यवधान)... यह टिप्पणी निकलवा जरूर दें ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं, नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, मैं यह कहने जा रहा था कि हमारे यहां पर जो नक्सलिज्म के आंकड़े बढ़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ की वजह से बढ़े हुए हैं। मैंने बताया है कि टोटल में से 47% इन्सिडेंट्स और 57% किलिंग्स एक ही जगह पर पड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी हम किसी एक स्टेट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनकी तकलीफों को समझते हैं। मगर इसके बाद भी यह बताने का एक प्रयास किया जाता है कि यह हो रहा है, उसका असर बुरा होता है। आंकड़े इस प्रकार से दे दिए जाते हैं कि उसके अंदर एक डर की भावना पैदा होती हे, टैररिज्म का मतलब ही है, डर की भावना पैदा करना ...(व्यवधान)... यह नहीं करना चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री अजय मारू: सर, आपने अपने प्रश्न के जवाब में कहा कि जहां पहाड़ हैं, वहीं पर आतंकवाद ज्यादा होता है। जिन प्रदेशों में भी आतंकवाद है, वे सब खनिज-सम्पदा से भरे हुए प्रदेश हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, उड़ीसा हो या आन्ध्र प्रदेश हो।

महोदय, इन्होंने कहा कि पिछले छ: वर्षों में सरकार ने 4000 करोड़ रुपये, 210 करोड़ रुपये और 1500 करोड़ रुपये की राशि इसके लिए दी, लेकिन इतनी बड़ी राशि देने के बाद अगर नकसलवाद कंट्रोल में नहीं आ रहा है और एक सांसद मारा जाता है तो सरकार इतनी बड़ी राशि देने के बाद उन राज्यों की मोनिटरिंग किस तरह से कर रही है?

श्री श्रीगोपाल व्यास: सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूं।

श्री सभापति: ठीक है, ये झारखंड से हैं।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, यह जो पैसे दिए जाते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए जाते हैं और उनको यह बताया जाता है कि अगर इन पैसों का खर्च इस प्रकार से होगा तो ठीक होगा, मगर वह पूरे तरीके से उन पर बंधनकारक नहीं होता है। उनको यह स्वतंत्रता भी दी जाती है कि वे किस प्रकार से दूसरे पैसों का इस्तेमाल करें। अब यहां पर जब सवाल आता है तो यह समझ कर आता है कि सारे गांवों में, सारे पुलिस स्टेशन्स में, दिल्ली सरकार की पुलिस ही काम कर रही है, यही समझकर सवाल आता है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि नक्सलाइड अफेक्टेड स्टेट में 33 बटालियन मैन आर्म्ड फॉर्सेस दिए, 33 बटालियन का मतलब होता है कि 33 हजार ऑफिसर्स हैं और इतने पैसे दिए हैं। और उसके बाद उनसे कहा गया है कि जो मैन पॉवर है, जो पैसा है, यह जो आपको हेलीकोप्टर दिए गए हैं या आपको आर्म्ड व्हीकल्स दिए गए हैं या नए हथियार दिए हैं उनका आप उपयोग कीजिए और उसका प्रयास करके उसको बंद कीजिए। मगर हम पूरी तरह से यह नहीं कहते हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी है, हम बिल्कुल ऐसा भी नहीं कहते, हमने कभी कहा भी नहीं है। मगर यहां प्रयास यह होता है कि दूसरे किसी की जिम्मेदारी नहीं है, केन्द्र सरकार की।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.